Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राष्ट्र निर्माण एवं शैक्षिणिक समस्याएँ एक अध्ययन

श्रीमती चित्रमाला भिमटे*

* सहा. प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शास. महाविद्यालय, लामता, जिला बालाघाट (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा विहीन समाज के विकसित राष्ट्र की कल्पना करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है शिक्षित समाज ही राष्ट्र विकास की अवधारणा को साकार कर सकने में समर्थ है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो पाना संभव है। यह शिक्षा ही है, जो एक आम व्यक्ति को समाज से अलग एक विशिष्ट स्थान दिलवाने का सामर्थ्य रखती है।

'साविद्या या विमुक्तये' अर्थात शिक्षा वहीं जो मुक्त करती है, मुक्ति का अर्थ तमाम बंधनों, अधविश्वायें। एवं कुरीतियों से मुक्ति पाना और नयी समझ के माथ नई दृष्टि का निर्माण करने से है। यदि सीधे तौर पर देखा जाय तो शिक्षा से सीधा लाभ ज्ञान और तथ्यों की समझ जागृत करना है न कि कुछ रटे तथ्यों की लम्बी सूची तैयार करना। अच्छी शिक्षा का मकसद मानव में सोचने तथा विचार करने की क्षमता पैदा करता है अपने आने वाले कुल के लिए ऐसी क्षमता पैदा कर सकना, जिसके माध्यम से ऐसे विषयों को अलग करने लायक हो जाए जिन पर ओर विचार करने की आवश्यक्ता है। यह छामता हग अच्छे अध्ययन से ही प्राप्त कर सकते हैं। यही अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जो हमें स्कूली तथा अन्य आगे की शिक्षाओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। बेहतर शिक्षा ही हमें वस्तु की परख करने की क्षमता प्रदान करती है।

शिक्षा ही वह माध्यम हे जो हमारे भीतर सही दृष्टिकोण, सही विचार तथा सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। जिससे हम अपने आपकों जीवन की विषम परिस्थितियों के अनुरुप आसानी से ढाल लेते हैं। शिक्षा जीवन में हमें मही फैमला लेने में मदढगार सिद्ध होती है आप प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी समस्यायों, तनाव तथा दुख से गुजरना पड़ता है। इनमें हग बच नहीं सकते किन्तु ऐसी परिस्थितियों का एक शिक्षित व्यक्ति बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। बल्कि ऐसी समस्याओं के भविष्य में आने पर स्वयं को पहले ही तैयार कर लेता है।

शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका न ही कोई आदि है और न ही अंत। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत रहता है बस यदि कुछ बदलता है तो वह है– शिक्षा का स्वरुप, माध्यमिक शिक्षा, उच्च तथा व्यावसायिक एवं तकनीकि शिक्षा इत्यादि। विकास और आधुनिकता की दौड़ में आगे बने रहने के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था है– प्रोफेशनल एजुकेशन यह पारम्परिक एकेडमिक एजुकेशन से सर्वदा भिन्न है यह समस्त शिक्षाएँ हमें अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाती है यही विशेषता राष्ट्र विकास के घटकों के रूप में प्रयुक्त होकर विकास व उन्नति को सुदृढ़ करती है।

शब्द कुंजी – राष्ट्र निर्माण, शिक्षा, विकास।

उद्देश्य:

1. राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के बढ़ते कदम का अध्ययन करना
2. शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन करना।
3. शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक समस्या के समाधान का अध्ययन करना।

अध्ययन की शोध प्रविधि – प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक संमको पर आधारित है, जिसमें मुख्य रुप से आकड़ों से संग्रहण हेतु शासकीय, पत्र–पत्रिकाओं, सख्यिकीय पुस्तिका, इन्टरनेट आदि का सहारा लिया गया है।

अध्ययन की प्रासंगिकता – प्रत्येक शोध कार्य का एक निश्चित उद्देश्य एवं प्रत्येक उद्देश्यपूर्ण कार्य का अपना महत्व होता है उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि आज शिक्षा का महत्व राष्ट्र निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण है शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिक्षाविदों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस शोध पत्र के माध्यम से शिक्षा सम्बंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा तथा इसमें उभरने का मार्ग प्रशस्त होगा।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षा के बढ़ते कदम – शिक्षा विकास का आधारमूलक सत्य है इसी शिक्षा रुपी साध्य से हम विकास रूपी साधन को प्राप्त कर सकते है। विश्व के लगभग सभी समाजों और कालों में शिक्षा का महत्व एक समान बना रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा के मामले में भी हमारी स्थिति अत्यंत चिन्तनीय थी, लेकित 1947 के बाद भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रभावशाली प्रयास हुए।

किसी भी राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक ने संयोजित होने वाले कारको में शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कारक है सुदृढ़ समाज के निर्माण में प्रारंभिक शिक्षा मजबूट नीव की भूमिका निभाती है अगर नींव ही कच्ची हो तो समाज के सृजनात्मक विकास की परिकल्पना करना संभव नही होता है।

सर्वप्रथम शिक्षा के महत्व को समझने एवं निवारण हेतु 1935 में केन्द्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया था। इसके पश्चात से प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास होते रहे। 1986 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम और 1992 में उसमें किये गये संशोधन तथा इसकी कार्ययोजना के अनुरुप सबको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पहल की गयी। 1994 यह कार्यक्रम देश के 7 राज्यों के 42 जिलों में लागू किया गया। ये 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गयी। 1985–1986 में प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने का कार्यक्रम शुरु किया

गया था। सन 2020 में नई शिक्षा नीति लागु की गई जिसमे आत्मनिर्भरता कौशल विकास उद्यमशीलता के द्वार सबके लिए खोल दिए गए।

भारत में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार भारी माजा में अनुदान देती है भारत में शिक्षित व्यक्ति का औसत जहाँ स्वतंत्रता पश्चात 1951 में मात्र 18.33 प्रतिशत था। वही सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति लगातार सजगता व प्रयास के कारण 1961 में 28.0 प्रतिशत तथा बर्ष 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार यह बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गया किन्तु बारीकी से अवलोकन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि यह अभी अन्य तमाम विकासशील देशों के औसत से काफी कम है।

भारत के साक्षरता की स्थिति

वर्ष	पुरुष	महिला	कुल साक्षरता
1961	40.36	15.33	28.33
1971	45.95	21.97	34.45
1981	56.38	29.76	43.57
1991	64.13	39.23	52.21
2001	75.86	54.16	65.38
2011	82.14	65.46	74.04

शैक्षणिक समस्याएँ:

1. अवैतनिक ओर कम योग्यता वाले शिक्षक– अवैतनिक व कम योग्यता वाले शिक्षक कई बार शासन वेतन समय पर उपलब्ध नहीं करवा पाती तथा उनकी आजीविका का एकमात्र साधन वही होता हे अत: वह शिक्षक का पद त्याग देते है। विशेष पाठ्यक्रम को पढने के लिए अलग से शिक्षकों की भती नहीं हो पाती।
2. आपूर्ति और वर्दी की लागत– आपूर्ति चोर नदी की लागत भूमि व विद्यार्थी को शक्षण के दौरान कि तीने व यूनिफॉम की नि:शुल्क व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे प्रवेश कम होते है।
3. लड़किया होना (लैंगिक भेदभाव)
4. प्रकोप और महामारी
5. मातृभाषा और साक्षरता का प्रभाव
6. शिक्षा में बुनियादी ढाँचे की कमी
7. वित्तीय संसाधन और शिक्षा तक पहुँच में असमानता
8. आनलाइन शिक्षा प्रणाली में असमानता
9. आर्थिक स्थिति कमजोर
10. विद्यालयों, महाविद्यालयो पर स्थानीय जवाबदेही की कमी
11. शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं विसंस्कृतीकरण
12. संकीर्ण शिक्षा प्रणाली एवं भौतिकतावादी दृष्टिकोण
13. नैतिक शिक्षा, मूल्य, आदर्श अप्रासंगिक हो चुके है।
14. शिक्षको की कमी – विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पूर्ति नहीं की जाती है जिससे सभी विद्यार्थिकी समस्या को हल कर पाना संभव नहीं हो पता है।

समाधान :

1. शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि।
2. पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक दृष्टिकोण पर तैयार करना।
3. शैक्षणिक अनुसंधानों पर विशेष जोर देना।
4. स्वायत्ता विद्यालयों तथा शिक्षण विभागों का विकास करना।
5. गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान प्रदान करना।
6. विद्यालय में कई पालियों में शिक्षण कार्य सम्पन्न करना।
7. छात्राओं के लिए विशेष सुविधाओ से युक्त होस्टल की व्यवस्था।
8. नेशनल ओपन स्कूल की तर्ज पर अधिक शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करना।
9. शिक्षण गुणवता को बनाये रखने के लिए औचक निरीक्षण की व्यवस्था।
10. शैक्षणिक व्यवस्था को पूर्णरुपेण पारदर्शी बनाना।
11. सिखने के विविध विकल्प प्रदान करना – विविध शिक्षण अवसर प्रदान करके शिक्षार्थी की जरूरतों और रुचियों को बेहतर ढंग से पूर्ण करने के लिए प्रयास करे।

निष्कर्ष – शिक्षा एक अनमोल रत्न है इसकी प्राप्ति जितनी ही हो, वह कम ही प्रतीत होगी जिस प्रकार रत्न शरुआत में पत्थर के आकार का होता है उसे बाद में जरूरत के अनुसार तराशकर अनमोल बना लिया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था को आवश्यक्ता और समय के साथ परिवर्तित कर अनमोल बनाया जा सकता है।

आज जरुरत इस बात की है कि स्कूली शिक्षा समाप्त कर जो युवा बाहर निकलते है, उनके अध्ययन के विषयों की बुनियादी जानकारी का व्यवहारिक पक्ष मजबूत हो। लोकतंत्र में राष्ट्र की जिम्मेदारी, नागरिको के कंधो पर होती है। यह वह तय करते हैं. कि उनक समाज का विकास किस दिशा में आगे बढ़े। इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए सुनिश्चत की गई शिक्षण व्यवस्था को क्या पुर्वमूल्यांकन की आवश्यक्ता है। यदि हाँ तो पुर्वमूल्यांकन का क्या आधार होगा क्या यह उद्देश्य के आधार पर सर्वसम्मत होगी या आवश्यक्ता के आधार पर ऐसे तमाम प्रश्न आज युवायों के जहन में है, जो कि कल के राष्ट्र निर्माता भी होगें।

शिक्षा का आधार चाहे जैसा भी हो किन्तु 21 वीं सदी की शिक्षण व्यवस्था में इस बात को ध्यान देना अनिवार्य है कि शिक्षा को आने वाले वाले समय में उद्योग तथा समाज से सीधे जोड़ा जाये। इसके लिए आवश्यक्ता होगी उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं की जिसके लिए एकेडमिक, औद्योगिक, और सरकारी तीनो क्षेत्रो को अपनी–अपनी भागीदारी ईमानदारी के साथ निभानी होगी। इन तीनों क्षेत्रो के संयुक्त प्रयास से, भारत की महाशक्ति बनकर विश्व पटल पर चमकेगा। जिसके लिए शिक्षा राष्ट्र विकास की कुजी के रूप में कार्य करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. बहादुर सिंह करुण, 'शिक्षा राष्ट्र विकास की कुंजी',कुरुक्षेत्र, पेज नम्बर (30–32) सितम्बर 2006
2. महेन्द्र सिंह यादव महेन्द्र,'मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में प्रारम्भिक शिक्षा का बदलता परिदृश्य', कुरुक्षेत्र, सितम्बर 2006, पेज नम्बर 34
3. कुंड प्रतिभा, 'शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रावधान', योजना, मार्च 2016 पेज नम्बर (59–62)
4. डॉ. चन्द्रपाल,'महिला शिक्षा के अनसुलझे पहलू', कुरुक्षेत्र मार्च 2005, पेज नम्बर (25–27)
5. जे. पी. सिंह,'शैक्षणिक पद्धति समाजशास्त्र : अवधारणाएँ एवं सिद्धांत', सन 2017 फिल लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।
6. कुमार पार्थिव:'शिक्षा हो आया ग्रामीण भारत में सामाजिक बदलाव', कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2015, पेज नम्बर–18
7. यादव प्रसाद बद्री के, भारतीय शिक्षा का स्वरुप समस्या और समाधान, बौद्ध अध्ययन विभाग दिल्ली, भारत 2021